भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2799

12 दिसंबर, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन का प्रभावी कार्यान्वयन

2799. श्रीमती कलाबेन मोहनभाई देलकरः
श्री रविन्द्र दत्ताराम वायकरः
श्री ज्ञानेश्वर पाटीलः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार का मुंबई, महाराष्ट्र और दादरा और नगर हवेली सहित देश भर में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम) कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से लागू करने और शहरी गरीबों की बड़ी आबादी तक पहुंचने के लिए वित्तपोषण की बाधाओं को किस प्रकार दूर करने का विचार है;

(ख) क्या एनयूएलएम ने रोजगार और टिकाऊ आजीविका सुनिश्चित करके शहरी गरीबों और उद्योग की आवश्यकताओं के बीच कौशल असंतुलन को दूर किया है;

(ग) यदि हां, तो दादरा और नगर हवेली और मध्य प्रदेश सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) देश में उक्त मिशन के तहत चल रहे कार्यक्रमों की निगरानी और मूल्यांकन में सुधार करने और इसकी पहलों के समग्र प्रभाव में सुधार करने के लिए प्रौद्योगिकी का अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग किस प्रकार किए जाने की संभावना है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क): 'भूमि' और 'कॉलोनीकरण' राज्य के विषय हैं और इसके अंतर्गत योजनाओं/कार्यक्रमों का कार्यान्वयन राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की जिम्मेदारी है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) "दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम)" के अंतर्गत केंद्रीय सहायता प्रदान करके राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में सहायता प्रदान करता है। महाराष्ट्र राज्य और दादरा और नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र सहित राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त आवश्यकताओं और उनके पास उपलब्ध धन के उपयोग के आधार पर योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उन्हें निधि जारी की गई हैं।

(ख) और (ग): मिशन के अंतर्गत कौशल प्रशिक्षण और रोजगार (ईएसटी एंड पी) घटक के माध्यम से रोजगार का उद्देश्य शहरी गरीबों को बाजार-उन्मुख पाठ्यक्रमों में कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है, जिससे उन्हें स्व-रोजगार उद्यम स्थापित करने या वेतनभोगी रोजगार सुरक्षित करने में सक्षम बनाया जा सके। इसके अतिरिक्त, स्व-रोज़गार कार्यक्रम (एसईपी) घटक लाभकारी स्व-रोज़गार उद्यम या सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने के लिए शहरी गरीब व्यक्तियों/समूहों/एसएचजी को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। मिशन के अंतर्गत, दिनांक 20.11.2024 तक, कुल 8,73,701 कौशल प्राप्त उम्मीदवारों को रोजगार मिल चुका है। दादरा और नगर हवेली और मध्य प्रदेश राज्य सहित जिन कौशल प्रशिक्षित उम्मीदवारों को नौकरी मिली है, उनका राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण अनुलग्नक I में संलग्न है।

(घ): योजना के अंतर्गत प्रगति की निगरानी एनयूएलएम-एमआईएस वेब पोर्टल के माध्यम से की जाती है। इसके अतिरिक्त, शहरी आजीविका ई-लर्निंग और रिसोर्स नेटवर्क (यू-लर्न), एक ई-लर्निंग टूल डीएवाई-एनयूएलएम पदाधिकारियों के कौशल और ज्ञान को बढ़ाने के लिए विकसित किया गया है। यह मोबाइल आधारित एप्लिकेशन के साथ-साथ वेब-आधारित प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त, मिशन के अंतर्गत लाभार्थियों को बैंक ऋण पर ब्याज छूट देने के लिए एक केंद्रीकृत ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म नामत: पोर्टल फॉर अफोर्डेबल क्रेडिट एंड इंटरेस्ट सबवेंशन एक्सेस (पैसा) पोर्टल विकसित किया गया है।

मिशन के योजना कार्य निष्पादन, निगरानी और मूल्यांकन को बढ़ाने और समग्र प्रभाव में सुधार के लिए, केन्द्रीय स्तर पर माननीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री (एमओएचयूए) की अध्यक्षता में एक गवर्निंग काउंसिल और आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में एक कार्यकारी समिति का गठन किया गया था। राज्य स्तर पर, मिशन की निगरानी एक गवर्निंग काउंसिल (जीसी) और कार्यकारी समिति (ईसी) द्वारा की जाती है। शहर/यूएलबी स्तर पर, मिशन की निगरानी नगर आयुक्त की अध्यक्षता में एक कार्यकारी समिति द्वारा की गई थी। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय ने योजना की प्रभावी निगरानी और मूल्यांकन के लिए राज्यों/यूएलबी के साथ नियमित सेमिनार, सम्मेलन, कार्यशालाएं आयोजित की।

******

अनुलग्नक ।

"राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन का प्रभावी कार्यान्वयन" के संबंध में दिनांक 12.12.2024 को उत्तर दिए जाने वाले लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2799 के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

डीएवाई-एनयूएलएम के अंतर्गत दिनांक 01.04.2014 से 20.11.2024 तक राज्यवार भौतिक प्रगति

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कौशल प्रशिक्षित रोजगार पाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0
2	आंध्र प्रदेश	74250
3	अरुणाचल प्रदेश	1792
4	असम	18816
5	बिहार	12945
6	चंडीगढ़	4416
7	छत्तीसगढ	16393
8	गोवा	4808
9	गुजरात	53627
10	हरियाणा	15483
11	हिमाचल प्रदेश	3881
12	जम्मू और कश्मीर	1538
13	झारखंड	52110
14	कर्नाटक	1732
15	केरल	16825
16	लद्दाख	0
17	मध्य प्रदेश	164908
18	महाराष्ट्र	113297
19	मणिपुर	9664
20	मेघालय	2101
21	मिजोरम	5151
22	नागालैंड	570
23	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	776
24	ओडिशा	4475
25	पुदुचेरी	406
26	पंजाब	49869
27	राजस्थान	24058
28	सिक्किम	340
29	तमिलनाडु	44954
30	तेलंगाना	17437
31	त्रिपुरा	783
32	उत्तर प्रदेश	120747
33	उत्तराखंड	9815
34	पश्चिम बंगाल	25734
	कुल	**8,73,701**

दादरा और नगर हवेली डीएवाई-एनयूएलएम के ईएसटीएंडपी और एसईपी घटकों को कार्यान्वित नहीं कर रहा था।